संपादक : विपिन मालवीया
✆ 94254.76757

संस्कृति

नर्मदापुरम • 13 मार्च 2025, गुरूवार • कुल पृष्ठ : 8 • आमंत्रण मूल्य : 2 रू

स्वच्छता पर रील बनाएं, लाखों के पुरस्कार पाएं

संस्कृति..... सिवनी मालवा

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत "स्वच्छ एमपी रील प्रतियोगिता" लॉन्च की गई है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में स्वच्छता एवं उससे जुड़े विषयों पर जागरूकता लाना और आमजन को इस अभियान से जोड़ना है।

तत्संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम श्री सौजान सिंह रावत ने बताया कि मध्य प्रदेश में कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए एक राज्य स्तरीय रील्स प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं, रचनाकर्मियों, और विद्यार्थियों को कचरा प्रबंधन से संबंधित विचारों और समाधानों को साझा करने के लिए प्रेरित करना है।

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी सुरक्षित अपशिष्ट निपटान से संबंधित वीडियो बनाकर अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन कर सकते हैं।

उक्त थीम एवं विषय पर आधारित रील्स को यूट्यूब एवं सोशल मीडिया प्लेटमॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं आधिकारिक स्वच्छ भारत वेबसाईट या पोर्टल जैसे प्लेटफार्म पर अपलोड करना होगा। वीडियो रील शेयर करने के लिए अपने वीडियो को Face-book / Youtube / instagram पर शेयर करें और उसके Link को mp.mygov.in पर सबमिट करें।

■ प्रतियोगिता के विवरण:

- थीम: "कचरा नहीं, यह कंचन है इसे अलग-अलग करें और पैसा कमाएँ"
- फॉर्मेट: 30 से 45 सेकंड तक का एचडी फॉर्मेट में रील्स (पोट्रेट फोर्मेट)
- भाषा: सरल हिंदी, स्थानीय भाषा
- विषय: प्रदेश के विभिन्न गाँव के लिए वेस्ट मैनेजमेंट पर रील्स बनाना, जिनमें मुख्य विषय गीला सूखा कचरा को अलग-अलग रखना, कचरे के दोबारा उपयोग, और खुले में कचरा नहीं फेंकना शामिल है।

- पुरस्कार:
- प्रथम पुरस्कार: 2 लाख रुपये
- द्वितीय पुरस्कार: 1 लाख रुपये
- तृतीय पुरस्कार: 50 हजार रुपये
- सांत्वना पुरस्कार (2): 25 हजार रुपये प्रत्येक

- प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए:
- मध्य प्रदेश के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं
- प्रतियोगिता के नियमों का पालन करना आवश्यक है
- प्रविष्टियां सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी
- इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी क्रिएटिविटी को उड़ान दें और अपने गाँवों को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाने की दिशा में अपनी रील्स के माध्यम से प्रस्तुत करें!

मध्यप्रदेश बजट २०२५-२६: प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाला बजटः प्रीति शुक्ला, भाजपा जिला अध्यक्ष

संस्कृति..... नर्मदापुरम

मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र के तीसरे दिन बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव की सरकार ने बजट पेश किया। प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ का बजट पेश किया है। बजट को लेकर नर्मदापुरम भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रीति शुक्ला ने प्रदेश के विकास को नई गति देने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें किसानों, महिलाओं, युवाओं और समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।

महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए बड़ा प्रावधान

जिला अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 18,669 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे प्रदेश की लाखों बहनें आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। वहीं, अनुसूचित जनजातियों के लिए 47,296 करोड़ रुपये और अनुसूचित जातियों के लिए 32,633 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे इन वर्गों का उत्थान सुनिश्चित होगा।

धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

उन्होंने कहा कि सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीकृष्ण पाथेय योजना के तहत 10 करोड़ रुपये और राम पथ गमन एवं चित्रकूट विकास परियोजना के लिए 30 करोड़ रुपये का बजट रखा है। साथ ही, ओंकारेश्वर लोक को महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा प्रदेश के धार्मिक और सांस्कृतिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी।

युवा और रोजगार को बढ़ावा

बजट में एमएसएमई और स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन देने की योजना है, जिससे प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

अविरल निर्मल नर्मदा योजना

नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए 'अविरल निर्मल नर्मदा योजना' की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत, नर्मदा तट से 10 किलोमीटर तक के वन क्षेत्रों में पौधारोपण किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण और नदी की स्वच्छता सुनिश्चित हो सके। साथ ही, नर्मदा परिक्रमा पथ पर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएगी, और आसपास के कृषि क्षेत्रों में जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा।

सड़क और बुनियादी ढांचा विकास

मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना के तहत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का विस्तार और सुधार करना है। अगले 5 वर्षों में प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें नर्मदापुरम जिले की सड़कों का भी समावेश होगा।

सिंचाई परियोजनाएँ

बजट में 19 वृहद एवं मध्यम और 87 लघु सिंचाई परियोजनाएँ प्रस्तावित हैं, जिनसे 7 लाख 2 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इन परियोजनाओं के लिए 17,863 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसका लाभ नर्मदापुरम जिले के किसानों को भी मिलेगा। इन घोषणाओं के माध्यम से नर्मदापुरम जिले में पर्यावरण संरक्षण, बुनियादी ढांचे का विकास और कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

साइबर स्मार्ट एस.एच.जी विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्कृति..... नर्मदापुरम

नर्मदापुरम कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में नवाचार की पहल की गई। जिसमें आई.आई.टी. मद्रास के प्रतिनिधियों द्वारा म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला पंचायत नर्मदापुरम अंतर्गत समस्त विकासखण्डों की महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों को सायबर अपराधों से बचाव विषय पर दो बैचों में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षकों द्वारा साइबर अपराधों से संबंधित विषयों जैसे मल्टीफेक्टर अथेन्टिकेशन, पासवर्ड सुरक्षा, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अज्ञात समूहों से स्वतः जुडने के बचाव एवं डिजीटल अरेस्ट, मोबाईल हैकिंग, साईबर स्टोकिंग से बचाव के उपाए, अंतर्राष्ट्रीय फाड कॉल से सावधानी, सोशल मीडिया पर गोपनीयता की सेटिंग को सीमित करना, ऋण के लिए आवेदन करने से पहले वैधता जाँचना और त्वरित ऋण धोखाधडी से बचाव, मोबाईल बैंकिंग यूपीआई बैंकिंग अंतर्गत फ्राड से बचने के उपाय, अज्ञात स्रोतो से ए.पी.के. फाईल डाउनलोड करने से बचाव, ऑनलाईन उत्पीडन या गतिविधियों के स्क्रीनशॉट और सबूत सुरक्षित रखने के तरीके इत्यादि पर विस्तार से प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा रूचि लेकर विषयवस्तु को समझा गया एवं विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित उनके अनुभव साझा किये।

प्रशिक्षण में जिले की लगभग 100 महिला स्व सहायता समूह सदस्यों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम श्री एस.एस. रावत ने बताया कि प्रशिक्षण बहुत ही लाभकारी एवं मील का पत्थर साबित होगा। भविष्य में सभी विकासखण्ड मे विषय से संबंधित मास्ट्रर ट्रेनर तैयार किये जाकर शत प्रतिशत समूह सदस्यों एवं ग्रामीण समुदाय को प्रशिक्षित किया जायेगा, जिससे हो रहे साइबर अपराधों से बचाव एवं सुरक्षा की जा सकें।

शासन के निर्देशानुसार उपार्जन प्रक्रिया प्रारंभ करनें के लिए आवश्यक व्यवस्थाऐं सुनिश्चित की जाए : कलेक्टर सोनिया मीना

संस्कृति..... नर्मदापुरम

बुधवार को कलेक्टर सोनिया मीना की अध्यक्षता में जिला उपार्जन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी उपार्जन प्रक्रिया को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। कलेक्टर ने निर्धारित तिथि के अनुसार उपार्जन कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए तथा उपार्जन केंद्रों के निर्धारण की स्थिति की समीक्षा की।

बैठक के दौरान कलेक्टर सुश्री मीना ने समिति के सदस्यों को निर्देशित किया कि आज शाम तक निश्चित संख्या के अनुसार गोदामों के प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि शासन की नीति के अनुसार ही गोदामों का निर्धारण किया जाए, जिससे उपार्जन कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके।

इसके अतिरिक्त, कलेक्टर ने गत वर्ष के खरीदी केंद्रों एवं जेवीएस गोदामों की स्थिति का आंकलन भी किया। कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए की एसडीएम तथा अन्य अनुविभाग स्तर के अधिकारियों को निश्चित संख्या अनुसार गोदामों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाए।

बैठक में जिला स्तरीय उपार्जन समिति के सदस्यों को यह भी निर्देशित किया गया कि तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को उपार्जन प्रक्रिया से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए निर्देश जारी किए जाएं।

बैठक के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सौजान सिंह रावत सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं उपार्जन समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

कलेक्टर सोनिया मीना ने विभिन्न विभागों की राजस्व वसूली की समीक्षा की, अधिकारियों को शीघ्र लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश दिए

संस्कृति.....नर्मदापुरम

बुधवार को कलेक्टर की अध्यक्षता में आबकारी, क्षेत्रीय परिवहन (आरटीओ), खनिज, पंजीयन एवं वाणिज्यिक कर विभाग की राजस्व वसूली एवं प्राप्तियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2024–25 की समाप्ति को दृष्टिगत रखते हुए आगामी दिनों में वसूली की कार्यवाही को गति प्रदान की जाए और निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की जाए।

बैठक के दौरान जिला आबकारी अधिकारी श्री अरविंद सागर ने बताया कि विभाग ने शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण कर लिया है। इसके साथ ही, जिले में 3 करोड़ 58 लाख रुपए की अवैध मदिरा जब्त की गई और 46 वाहनों को भी जप्त किया गया। उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2024–25 के दौरान 9 34(2) के अंतर्गत विभिन्न प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं।

कलेक्टर ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए कि अनफिट वाहनों पर नियमित कार्रवाई जारी रखी जाए और नगर पालिका के साथ समन्वय स्थापित कर जाम एवं अवैध पार्किंग की समस्या के समाधान हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने सड़क सुरक्षा समिति की मासिक एवं त्रैमासिक बैठकों का नियमित आयोजन करने के निर्देश भी दिए।

पंजीयन विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने निर्देशित किया कि वित्तीय वर्ष समाप्ति से पूर्व लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए।

बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि राजस्व वसूली में तेजी लाते हुए वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करें।

शासन के निर्देशानुसार उपार्जन प्रक्रिया प्रारंभ करनें के लिए आवश्यक व्यवस्थाऐं सुनिश्चि की जाए : कलेक्टर सोनिया मीना

संस्कृति.....नर्मदापुरम

बुधवार को कलेक्टर सोनिया मीना की अध्यक्षता में जिला उपार्जन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी उपार्जन प्रक्रिया को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। कलेक्टर ने निर्धारित तिथि के अनुसार उपार्जन कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए तथा उपार्जन केंद्रों के निर्धारण की स्थिति की समीक्षा की।

बैठक के दौरान कलेक्टर सुश्री मीना ने समिति के सदस्यों को निर्देशित किया कि आज शाम तक निश्चित संख्या के अनुसार गोदामों के प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि शासन की नीति के अनुसार ही गोदामों का निर्धारण किया जाए, जिससे उपार्जन कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके।

इसके अतिरिक्त, कलेक्टर ने गत वर्ष के खरीदी केंद्रों एवं जेवीएस गोदामों की स्थिति का आंकलन भी किया। कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए की एसडीएम तथा अन्य अनुविभाग स्तर के अधिकारियों को निश्चित संख्या अनुसार गोदामों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाए।

बैठक में जिला स्तरीय उपार्जन समिति के सदस्यों को यह भी निर्देशित किया गया कि तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को उपार्जन प्रक्रिया से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए निर्देश जारी किए जाएं।

बैठक के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सौजान सिंह रावत सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं उपार्जन समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

किसानो को दी गई उन्नत कृषि तकनीक की जानकारी

संस्कृति..... नर्मदापुरम

सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन "आत्मा" योजना अंतर्गत जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन 12 मार्च 2025 को कृषि विज्ञान केंद्र गोविंदनगर बनखेड़ी में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा श्री अजीत सिंह मंडलोई सभापति जिला कृषि स्थाई समिति, जिला पंचायत नर्मदापुरम के मुख्य आथित्य में आयोजित किया गया । कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष बनखेड़ी श्रीमती पूनम पटेल, उपाध्यक्ष भाऊसाहाब भुस्कुटे स्मृति लोक न्यास गोविंदनगर श्री उमेश सिंह पटेल, श्री मकरान सिंह पटेल, श्रीमती पूजा अग्रवाल, सहसचिव श्री केशव माहेश्वरी, कोषाध्यक्ष श्री शैलेंद्र जैन, बोर्ड मेंबर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद श्री नीति राज पटेल, उपसंचालक कृषि श्री जे.आर हेडाऊ, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनीशा श्रीवास्तव, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद बेड़ा, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक खांडे, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार गर्ग एवं भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री लोकेंद्र सिंह राजपूत एवं जिला नर्मदापुरम के विभिन्न विकासखंडो से आए हुए किसान बंधु उपस्थित रहे साथ ही आभासी रूप से क्षेत्रीय लोकप्रिय सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।

उपसंचालक कृषि द्वारा कार्यक्रम का परिचय एवं रूपरेखा से अवगत कराते हुए बताया गया कि इस कृषि विज्ञान मेले का उद्देश्य किसानों के बीच उन्नत कृषि तकनीक एवं जैविक प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करना है। किसानों से आग्रह किया गया की ग्रीष्मकालीन मूंग को शीघ्र पकाने या सूखने के लिए निंदानाशक रसायन विशेष कर ग्लाइकोसाइड, पैराक्वेट का प्रयोग ना करें। मूंग फसल में इन रसायनों के प्रयोग से हमारे पर्यावरण के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, मूंग की बोनी विलंब से ना करें।

किसान भाई ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल में अत्यधिक मात्रा में कीटनाशी रसायनों का प्रयोग ना करें। मूंग की फसल में आवश्यकता पड़ने पर ही अनुशंषित मात्रा में रसायनों का प्रयोग करें तथा जैविक व प्राकृतिक विधियों से तैयार निमास्त्र, जीवामृत, बीजाअमृत, घनजीवा अमृत आदि के प्रयोग से विषरहित स्वास्थ्य वर्धक अनाज का उत्पादन करें। लोकसभा सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी द्वारा मेले के किसानों को वर्चुअल संबोधित कर श्री अन्न मिलेट्स की खेती तथा प्राकृतिक व जैविक खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया। सांसद द्वारा बताए गया कि हमारा जिला मूंग एवं गेहूं के उत्पादन में हमेशा से ही अग्रणी जिला रहा है, उन्होंने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए जमीन स्तर पर क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओ और व्यवस्थाएं जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी सिंचाई व्यवस्था, बिजली व्यवस्था के संबंध में त्वरित किसान हितेषी निर्णय लिए जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का आभार व्यक्त किया।

सांसद प्रतिनिधि एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बोर्ड मेंबर श्री नीति राज पटेल के द्वारा किसानों को संबोधित कर बताया गया कि आप किसान भाइयों के सहयोग से मोटे अनाज जैविक खेती कर मानव समाज व प्रकृति को सुरक्षित व संरक्षित किया जा सकता है।

श्री उम्मेद सिंह पटेल द्वारा बताया गया कि जिस तरह किस तरह से मैं अपने परिवार एवं समाज के लिए जैविक खेती कर रहा हूं वैसे ही आप भी अपने खेत के लिए छोटे से रकबे में जैविक खेती की शुरुआत करें और अपने परिवार के सदस्यों को रासायनिक विषमुक्त भोजन परोसे।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पिपरिया अनिषा श्रीवास्तव ने किसानों को कृषि विज्ञान मेले के माध्यम से कृषि में वैज्ञानिक तकनीके सीख कर अपनी कृषि में उपयोग कर उन्नत खेती करें एवं भूमि की सुरक्षा एवं उर्वरता को बनाए रखने के दायित्व के प्रति जागरूक किया।

श्री अजीत मंडलोई कृषि स्थाई समिति द्वारा फसलों में जहरीली दवाओं का इस्तेमाल कम से कम कर जैविक एवं प्राकृतिक खेती करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

तकनीकी सत्र के दौरान डॉक्टर संजीव कुमार गर्ग द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका एवं नरवाई प्रबंधन व प्राकृतिक खेती की कृषि की पद्धति की जानकारी दी गई। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक खांडे द्वारा ग्रीष्मकालीन मूंग उत्पादन तकनीक एवं मूंग की खेती में रसायनों का कम से कम उपयोग करें तथा एक ही प्रकार के कीटनाशक का प्रयोग बार बार न करके अलग-अलग प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग करने की सलाह दी गई। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद बेड़ा द्वारा फसलो की उन्नतशील किस्मो की जानकारी दी गई। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बृजेश कुमार नामदेव द्वारा जैविक पोध संरक्षण पर जानकारी प्रदान की गई।

कार्यक्रम में कृषक वैज्ञानिक संवाद के दोरान कृषक श्री भूपेन्द्र पटेल द्वारा अपने जैविक एवं प्राकृतिक खेती के अनुभव के किए गए। उसी के साथ साथ कृषक श्री रमेश मेहरा, प्रमोद दुबे एवं श्री शरद वर्मा द्वारा भी अपने जैविक एवं प्राकृतिक खेती के अनुभव साझा किए गए।

कार्यक्रम में 30 से अधिक कृषि प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें कृषि एवं कृषि से संबंधित विभाग एवं कृषि से जुड़ी संस्थाओं द्वारा कृषि आदान, उत्पाद एवं उन्नत तकनीको का जीवंत प्रदर्शन किया गया एवं जिले के प्रगतिशील कृषको के द्वारा भी किया जा रहे उत्पादित फसलों की प्रदर्शनी लगाई गई।

अंत में "आत्मा" योजना अंतर्गत सर्वोत्तम जिला स्तरीय,विकासखंड स्तरीय एवं सर्वोत्तम कृषक समूह के पुरस्कार के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कृषि विज्ञान केंद्र में किया जा रहे हैं उन्नत कार्य हेतु आर्या परियोजना के अंतर्गत हितग्राही कृषकों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में प्रदर्शनियां तथा कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में लगाए गए उन्नत कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन डॉक्टर संजीव गर्ग, डॉ राजेंद्र पटेल द्वारा अतिथियों को करवाया गया।

नर्मदापुरम में यातायात पुलिस ने अवैध हूटर हटाए, लगाया जुर्माना

संस्कृति..... नर्मदापुरम

पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार नर्मदापुरम ट्रैफिक पुलिस द्वारा हूटर, पदनाम वाले प्लेट व रंगीन लाईट वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है जिसमे आज 10 हूटर लगे हुए वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई जिसमें 9 वाहनों से जुर्माना 27000 वसूल किया गया है जबकि जुर्माना जमा न करने पर एक शासकीय कार्यालय में संबद्ध अनधिकृत हूटर वाले वाहन

का प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है 55 पदनाम प्लेट वाले वाहनों पर अभी तक कार्यवाही की गई है।। अन्य धाराओं में भी आज 8 वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही कर जुर्माना 4600 अलग से वसूला गया है यह कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी।। यातायात पुलिस की अपील है कि असुविधा से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करे

मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी को "जीवित इकाई" घोषित किया जाए: माया नारोलिया

संस्कृति..... नर्मदापुरम

नर्मदापुरम - राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया ने दिल्ली में सदन के माध्यम से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने ध्यान आकर्षित करते हुए सदन में कहा कि नर्मदा नदी केवल एक जलधारा नहीं बल्कि मध्यप्रदेश और गुजरात के करोड़ों लोगों की जीवनरेखा है। यह नदी प्रदेश के 16 जिलों से होकर बहती है और इसकी जलधारा पर लाखों किसान, श्रद्धालु एवं स्थानीय समुदाय निर्भर हैं। मैं सरकार द्वारा

नदियों की सफाई और संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की सराहना करती हूँ। नमामि गंगे कार्यक्रम और विभिन्न राज्य स्तरीय नदी पुनर्जीवन पहल ने पर्यावरण संतुलन बहाल करने और स्वच्छ जल संसाधनों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हालाँकि मैं इस सदन का ध्यान मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी की गंभीर स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। मध्य भारत की जीवनरेखा मानी जाने वाली यह नदी अत्यधिक रेत खनन, वनों की कटाई और अनियंत्रित प्रदूषण के कारण संकट में है। राज्य सरकार द्वारा नर्मदा सेवा मिशन के तहत सराहनीय कदम उठाए गए हैं, लेकिन पर्यावरण कानूनों को सख्ती से लागू करने, सतत जल प्रबंधन और जनसहभागिता को बढ़ावा देने की अत्यधिक आवश्यकता है।

इसी तर्ज पर, मैं सरकार से माँग करती हूँ कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को ?जीवित इकाई? घोषित किया जाए। जिससे इसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस कदम से नर्मदा का प्राकृतिक प्रवाह, उसकी जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत को बचाने में मदद मिलेगी। मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि वह इस पवित्र नदी को जीवित करने के लिए अधिक संसाधन आवंटित करे और एक समग्र पुनर्जीवन योजना लागू करे, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।

आगामीं होली व अन्य त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए थाना क्षेत्रों में निकाला फ्लैग मार्च

संस्कृति..... सिवनी मालवा

पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह के निर्देशन में आगामीं होली एवं अन्य त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए थाना क्षेत्रों में निकाला गया फ्लैग मार्च। होटलों/ धर्मशालाओं / रेलवे स्टेशन आदि में की जा रही सघन चैकिंग। रात्रि गश्त में फालतू घूम रहे युवाओं से पूँछताँछ कर की जा रही वैधानिक कार्यवाही। पुलिस

महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना जी के निर्देशानुसार नर्मदापुरम पुलिस द्वारा जिले के समस्त थाना/चौकी क्षेत्र में आगामी होली एवं अन्य त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु सक्रिय कार्यवाही की जा रही है । पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम डॉ. गुरकरन सिंह द्वारा आगामी होली एवं अन्य धार्मिक त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए समस्त थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्र में शाम एवं रात्रि में पैदल गश्त करते हुये अवैध गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने हेतु एवं फ्लैग मार्च करने हेतु निर्देशित किया गया है । इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम डॉ. गुरकरन सिंह के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष मिश्र के मार्गदर्शन में नर्मदापुरम कोतवाली एवं देहात पुलिस द्वारा एरिया डॉमिनेशन हेतु फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस लाइन नर्मदापुरम,थाना कोतवाली नर्मदापुरम एवं थाना देहात के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया गया।

भारतीय रेल के आधुनिकीकरण और विस्तार के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता अत्यंत सराहनीय रही: माया नारोलिया

संस्कृति..... सिवनी मालवा

नर्मदापुरम - राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया ने दिल्ली में सदन के माध्यम से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने ध्यान आकर्षित करते हुए सदन में कहा कि भारतीय रेल के रूपांतरण पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ी हुई हूँ। यह परिवर्तन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और हमारे कर्मठ रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के प्रभावी प्रयासों के कारण संभव हुआ है। भारतीय रेल के आधुनिकीकरण और विस्तार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अत्यंत सराहनीय रही है, और मैं इस क्षेत्र में सरकार की उल्लेखनीय उपलब्धियों को साझा करने में गर्व महसूस कर रही हूँ।

हालाँकि, इन उपलब्धियों का उत्सव मनाते समय, हमें अतीत को भी याद रखना चाहिए। पिछली सरकारों ने दशकों तक रेलवे की उपेक्षा की। परियोजनाएँ लंबित रहीं, सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज किया गया, और आधुनिकीकरण की गति धीमी रही।

उदाहरण के लिए, 2009 से 2014 के बीच रेलवे में वार्षिक निवेश औसतन केवल ₹45,000 करोड़ था, जबकि 2025 में यह राशि ₹2.55 लाख करोड़ तक पहुँच गई है। नतीजतन, उस समय की रेलवे व्यवस्था देश की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ रही। आज, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारतीय रेलवे न केवल उन चुनौतियों से उबर चुकी है, बल्कि नवाचार और दक्षता के लिए एक वैश्विक मानक भी बन गई है।

अंत में, मैं यह दोहराना चाहूँगी कि भारतीय रेलवे केवल एक परिवहन माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि यह भारत की विकास गाथा का प्रतीक बन गई है। बजट 2025 के माध्यम से, सरकार ने फिर से यह सिद्ध किया है कि वह एक 'नए भारत' के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है—एक ऐसा भारत जो जुड़ेगा, आधुनिक बनेगा और आत्मनिर्भर बनेगा। मैं इस सदन के सभी सदस्यों से इन परिवर्तनकारी पहलों का समर्थन करने और विश्व स्तरीय भारतीय रेलवे के निर्माण में योगदान देने का आह्वान करती हूँ।

माया नारोलिया, राज्यसभा सांसद

- विद्युतीकरण: 2023 तक भारतीय रेलवे के ब्रॉड-गेज नेटवर्क का 85% से अधिक विद्युतीकरण हो चुका है, जबकि 2014 में यह केवल 45% था। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसने भारतीय रेल को दुनिया के सबसे बड़े हरित रेल नेटवर्क में शामिल कर दिया है।
- नई पटरियाँ और दोहरीकरण: 30,000 किलोमीटर से अधिक नई रेल पटरियाँ बिछाई गई हैं, और 15,000 किलोमीटर से अधिक मार्गों पर दोहरीकरण/तिहरीकरण पूरा किया गया है, जिससे भीड़भाड़ कम हुई है और दक्षता में वृद्धि हुई है।
- वंदे भारत ट्रेनें: 2024 तक 51 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो चुकी है, जो विश्व स्तरीय सुविधाओं और 160-180 किमी/घंटे की गति से रेल यात्रा को नए स्तर पर ले गई हैं।
- मालवाहन गलियारे: 2,800 किलोमीटर लंबे पूर्वी और पश्चिमी समर्पित मालवाहन गलियारे लगभग पूर्ण होने के कगार पर हैं, जिससे मौजूदा रेल मार्गों की भीड़ कम होगी और भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।
- मध्य प्रदेश, मेरा गृह राज्य, भी इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण लाभार्थी रहा है। इटारसी-नागपुर लाइन के दोहरीकरण, भारत के पहले विश्व-स्तरीय स्टेशन हबीबगंज (रानी कमलापति रेलवे स्टेशन) के पुनर्विकास और भोपाल, इंदौर, जबलपुर को जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत से राज्य के लोगों को अत्यधिक सुविधा मिली है।
- इसके अतिरिक्त, उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक और दुनिया के सबसे ऊँचे रेलवे पुल—चिनाब ब्रिज—जैसी इंजीनियरिंग उपलब्धियाँ मोदी सरकार की दूरदृष्टि को दर्शाती हैं, जिसने दुर्गम क्षेत्रों तक रेल कनेक्टिविटी सुनिश्चित की है।
- वर्ष 2025 का रेल बजट इस मजबूत नींव पर आगे बढ़ रहा है। रेल क्षेत्र के लिए ₹2.65 लाख करोड़ के ऐतिहासिक आवंटन के साथ, सरकार ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं:
  - 400 नई वंदे भारत ट्रेनें: इससे देशभर में कनेक्टिविटी और यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
  - 'कवच' एंटी-कोलिजन सिस्टम: इस स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार उच्च घनत्व वाले सभी रेल मार्गों तक किया जाएगा, जिससे रेल यात्रा अधिक सुरक्षित होगी।
  - अमृत भारत स्टेशन योजना: 1,300 स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना है, जिससे आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी और यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी।
  - हरित पहल: भारतीय रेलवे 2030 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। सौर ऊर्जा से संचालित स्टेशन, जैव-शौचालय, और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग जैसी पहल इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होंगी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक विपिन मालवीया, द्वारा श्री सिद्धिविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं 26 बी, देशबंधू परिसर, प्रेस कम्प्लेक्स, एमपी नगर जोन - 1, भोपाल से मुद्रित तथा म नं 51, जेल रोड, सिवनी मालवा, इटारसी/नर्मदापुरम, जिला नर्मदापुरम से प्रकाशित। मोबाइल नंबर - 9425476757, Title: MPMUL0382